वाहन उद्योग के लिए आज पीएलआई योजना संभव

तैयारी

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

केंद्र सरकार बुधवार को ऑटो सेक्टर के लिए करीब 57 हजार करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे सकती है। इस योजना के तहत न सिर्फ ऑटो कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने में सहारा मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी भारत की पकड़ और मजबूत होगी। साथ ही देश में नौकरियों के मौके भी बढ़ेंगे।

हिन्दुस्तान को सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक आठ सितंबर को संभावित कैबिनेट बैठक में इसे अंतिम मंजूरी दी जा सकती है। भारी उद्योग मंत्रालय ने इस बारे में प्रस्ताव तैयार करके केबिनेट को भेज दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इस बारे में तैयारी की जा रही थी। इससे जुड़े विभागों और नीति आयोग के बीच भी कई दौर की बातचीत में योजना पर मंथन किया गया था। साथ ही कैबिनेट सचिव की अगुवाई में हुई बैठक में भी इसके स्वरूप को मंजूरी मिल चुकी है। उल्लेखनीय है कि देश का वाहन क्षेत्र पिछले कई साल से सुस्ती का सामना कर रहा है। कोरोना संकट ने इसे और बढ़ा दिया है। इसके मद्देनजर सरकार वाहन क्षेत्र को गति देने के लिए चौतरफा प्रयास कर रही है। वाहन क्षेत्र की बड़ी कंपनियों से एमएसएमई क्षेत्र की हजारों कंपनियां जुड़ी हैं। वाहन क्षेत्र में पीएलआई से एमएसएमई को भी फायदा होगा। साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ने और निर्यात में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। उद्योग के अनुमान के अनुसार एक वाहन के निर्माण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तीन लोगों को रोजगार मिलता है।

सेमीकंडक्टर की कमी से वाहनों की आपूर्ति घटेगी: फाडा

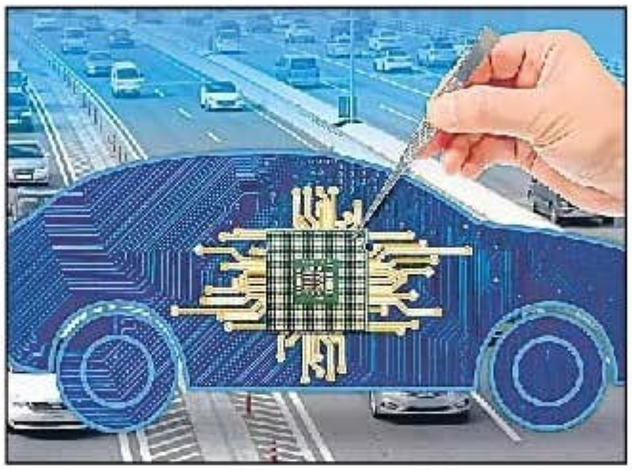

चिप की कमी की वजह से त्योहारी सीजन के दौरान यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री पटरी से उतर सकती है। वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने यह आशंका जताई है। इस समय सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से वाहन कंपनियां डीलरों को आपूर्ति पर्याप्त रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। फाडा ने सेमीकंडक्टर की कमी को एक बड़ा संकट करार देते हुए कहा कि विशेषरूप से यात्री वाहनों के डीलरों के लिए त्योहारी सीजन ठंडा रहेगा। इससे डीलरों के पास पर्याप्त भंडार नहीं होगा और त्योहारी सीजन में उनके पास मॉडलों की उपलब्धता कम रहेगी।